संख्या- 87 /2018 / 1533 /चार-2018 -59 (बजट)/ 2018

प्रेषक,

लुटावन राम
उप सचिव ,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 13 जून, 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में संत कबीर अकादमी की स्थापना आदि कार्य हेतु प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-536/0सं0नि0-6(कबीर अकादमी)/2018-19 दिनांक 25 मई, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में संत कबीर अकादमी की स्थापना आदि कार्य हेतु रू0 2359.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति एवं रू0 250.00 लाख (रूपये दो करोड पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(2) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, संस्कृति का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, संस्कृति द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के साथ-साथ वित्ती हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय -12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(4) कार्य की विशिष्टियॉ, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, संस्कृति की होगी तथा निदेशक, संस्कृति यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाय।

(5) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अत: इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(vii) में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) यह अनिवार्य रूप में सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यो की मानीटरिंग भी किया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(8) प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में निदेशक, संस्कृति द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, संस्कृति का होगा।

(9) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(10) पी0एफ0ए0डी0 के द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

(11) निदेशक, संस्कृति द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(12) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप निदेशक, संस्कृति द्वारा सक्षम आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय। उक्त कार्य हेतु सुरक्षा की दृष्टिगत से अग्निशमन विभाग की अनापत्ति प्राप्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(13) प्रायोजना प्रस्ताव में प्रस्तावित कतिपय कार्यमदें यथा- ट्रान्सफारमर , डी0जी0 सेट, आडिटोरियम साउण्ड , लाइटिंग सिस्टम आडीटोरियम चेयरस, सिन्थेटिक कारपेट, वालपेनेलिंग व फर्नीचर आदि की दरें एकमुश्त आधार पर प्रस्तावित की गयी है। प्रभाग का मत है कि क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यो हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार कोटेशन प्राप्त करें, चूॅकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य है एवं इनके शिड्यूल ऑफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेशिफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अत: निदेशक, संस्कृति से अपेक्षित है कि निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधारपर किया जाय।

(14) प्रायोजना प्रस्ताव में प्रस्तावित मात्राओं तथा प्राविधानों को कार्यान्वयन के समय सुनिश्चित किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, संस्कृति/कार्यदायी संस्था का होगा।

(15) प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय। प्रभाग का यह भी मत है कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति /द्विरावृत्ति न हो इसे अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे।

(16) प्रायोजनान्तर्गत पावर कनेक्शन हेतु रू0 15.00 लाख की धनराशि प्रस्तावित की गयी है, जिसे प्रभाग द्वारा यथावत अनुमन्य किया गया है जो विद्युत विभाग के सक्षम स्तर से अनुमोदित विस्तृत आगणन के आधार पर देय होगी।

(17) प्रभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है। जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढाना, कार्यो के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि , सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(18) प्रायोजना प्रस्ताव में प्रस्तावित कतिपय कार्यमदें यथा-आडिटोरियम चेयर्स लागत, आडिटोरियम साउण्ड सिस्टम , स्टेज लाईट व फर्नीचर की दरें एकमुश्त आधार पर प्रस्तावित की गयी है। प्रभाग का मत है कि इन कार्यमदों की आवश्यकता, औचित्य स्पेसिफिकेशन एवं लागत हेतु प्रमुख सचिव/सचिव, संस्कृति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाय। यह समिति इन कार्यमदों की आवश्यकता, औचित्य स्पेसिफिकेशन एवं लागत का परीक्षण कर स्वयं संतुष्ट हो लेगी। प्रायोजना में पी0एफ0ए0डी0 द्वारा आकलित लागत सीमा रू0 190.44 लाख के अन्तर्गत उक्त समिति जो लागत संस्तुत करेगी, इस संस्तुत लागत की सीमा तक प्रयोजना की लागत संशोधित मानी जायेगी। प्रायोजना की संशोधित लागत हेतु प्रायोजना को पुन: सक्षम स्तर के विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

(19) प्रायोजनान्तर्गत सम्पादित कार्यो की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व निदेशक, संस्कृति निदेशालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(20) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(21) निदेशक, संस्कृति द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30 मार्च, 2018 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3 - उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-92- के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-04-कला तथा संस्कृति-800-अन्य व्यय-03-प्रेक्षागृह/खुलामंच का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई- 7-551 /दस-2018 दिनांक 11 जून, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(लुटावन राम)
उप सचिव

संख्या- 87 /2018/ 1533 /चार-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद , नीलिगिरी काम्पलेक्स इन्दिरानगर लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रयक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग/नियोजन अनुभाग-4,
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लुटावन राम)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।